

which could be taken up earlier than that we should not do so or we should not consider that. Specially in respect of Andhra, as the hon. Deputy Minister has said, the committee has already submitted its report and it has been sent to the Andhra Government. I fully realise the necessity of setting up a fertiliser factory in Andhra. It is one of our surplus States and it is necessary that we should help Andhra in the matter of setting up a fertiliser plant in that State. Besides that there are other States also. In a general way I would like to say that I would very much like that almost every State should have a fertiliser plant. Unless of course there is some basic difficulty, for example, shortage of raw material or other things, we would very much like that each State should have at least one fertiliser factory so that they can help in stepping up the agricultural production as well as the cash crops which are absolutely necessary for the improvement of exports of agricultural products.

Shri Ram Krishan Gupta: From the statement I find that they have also examined sites in Assam. May I know the names of the sites which were visited by this committee in Assam?

Shri Satish Chandra: Three sites were investigated by the Committee in Assam. One was in the vicinity of Nahorkatiya oil-field, another in the vicinity of Moran oil-field and the third in Gauhati. The consensus of opinion in the Committee is that Nahorkatiya would be the most suitable site.

Shri Sinhasan Singh: Just now the hon. Minister has said that Andhra is going to be given preference because it is a surplus State. May I know whether the policy of the Government is to provide fertiliser factories in surplus States or in deficit States?

Shri Lal Bahadur Shastri: What I said was to give one to all the States but at least that State should be helped which might help in feeding Uttar Pradesh which is a deficit province.

Shri Heda: The statement tells us that a site has been selected in Andhra Pradesh at Kothagudium. What would be its capacity and would the project be in the public sector or in the private sector? Has any progress been made in starting the factory?

Shri Satish Chandra: The proposal is to produce 80,000 tons of nitrogen at Kothagudium. The Committee have recommended that 45,000 tons of this nitrogen should be converted into urea and 35,000 tons into nitro phosphate. The same proposal has come from the Andhra Government. Whether it would be in the State sector, the Central sector or in the private sector is a matter to be decided later on.

सेठ गोविन्द दास : जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, क्या हुशंगाबाद जिले में इटारसी में इस प्रकार की फ़ैक्टरी बनाने की कोई योजना चल रही है और क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अर्ज किया कि कमेटी राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जायेगी । वहां पर दो स्थान हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है । एक इटारसी है जहां कि करीब में कोयले की खानें हैं और इससे फर्टिलाइजर बन सकते हैं । दूसरी सम्भावना फर्टिलाइजर पैदा करने की भिलाई में है । दोनों के ऊपर कमेटी गौर कर के फिर राय देगी कि कहां कौन सी बेहतर जगह होगी ।

बिहार में अशोक पेपर मिल्स

*१०१८. पंडित द्वा० ना० तिवारी
क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरभंगा, बिहार के ममीप "अशोक पेपर मिल्स" के नाम से

एक नये कारखाने की स्थापना के लिये एक भारतीय फर्म को लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) किन-किन देशों से पूंजी उपकरण मंगाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

मै० श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि०, कलकत्ता को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक लाइसेंस दिया गया है। इसके अनुसार "अशोक पेपर मिल्स लि०" नाम से दरभंगा, बिहार में एक नया कारखाना खोला जायेगा जिसमें लिखाई तथा छपाई का १५,००० टन कागज और १६,५०० टन लुगदी प्रति वर्ष बना करेगी। यह कारखाना १९६१ के अन्त तक स्थापित हो जाने की संभावना है। इसके लिये २०० लाख रु० के पूंजीगत उपकरण आयात करने की आवश्यकता होगी। इन में से कुछ उपकरण अमेरिका से निर्यात आयात बैंक ऋण योजना के अधीन और कुछ उपकरण फ्रांस से फ्रांसीसी ऋण योजना के अन्तर्गत आयात किये जायेंगे। उपकरण देने वाली फ्रांसीसी कम्पनी इस योजना की पूंजी में ३० लाख रुपये लगायेगी।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मै जानना चाहता हूँ कि इस फैक्टरी में कितनी पूंजी लगेगी और गवर्नमेंट से क्या उन लोगों ने जिनके कि नाम लाइसेंस मिला है, उन्होंने कर्ज के लिये भी दरखवास्त दी है और यदि हां तो कितना कर्ज सेंकशन हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : इसकी पूंजी कोई ४, ५ करोड़ रुपये तक होगी। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का ताल्लुक है उसने कोई डाइरेक्ट असिस्टेंस या मदद नहीं मांगी है लेकिन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से और बैंकों से जो भी नियम के अधीन सहायता दी जा सकती है वह जरूर उनको मिलेगी।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमान् यह बताने का

Mr. Speaker: The hon. Member is going on changing from place to place. He was sitting there. Today he is sitting here.

श्री राम सिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमान् यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस फैक्ट्री की पर डे क्या कैपेसिटी है ?

श्री मनुभाई शाह : ५० टन है।

Shri Shree Narayan Das: By what time this firm will be able to produce paper?

Shri Manubhai Shah: Within three years.

Export of Iron Ore

*1019. Shri Panigrahi: Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1316 on the 17th September, 1959, and state:

(a) whether the anticipated exports of iron ore from the various ports in India for 1958-59 had been completed; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra):

(a) No, Sir.

(b) The buyers failed to lift the contracted quantities according to agreed schedule of delivery.

Shri Panigrahi: May I know by what time these anticipated targets of export from these ports are going to be completed?